



कानपुर शनिवार 17 अक्टूबर, 2026

वर्ष: 03, अंक: 249, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com



सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

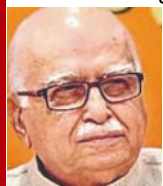
नकली सीमेंट के खेल में राजनीतिक मिलावट !...>Pg3 मूल्य: 2 ₹

इनसाइड भारत पर टला 100% टैरिफ...>Pg12

खबर: एक नजर में

लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री



लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण के कारण दिल्ली के इंदिरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शुक्रवार, 16 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, 98 वर्षीय आडवाणी का पल्मोनरी विभाग में उपचार चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है।

अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, तीन की मौत

अमेरिका। ओरेगन राज्य के बेंड शहर स्थित सिल्वर रेल प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार (15 अक्टूबर) को हुई गोलीबारी में तीन बच्चों और एक शिक्षिका की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हमले में पांच, आठ और 11 वर्ष के बच्चों की जान गई। 25 वर्षीय शिक्षिका मेगन लैम्बर्ट भी मृतकों में शामिल हैं। हमले में एक अन्य बच्चा और 54 वर्षीय शिक्षिका घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, 16 वर्षीय हमलावर ने विद्यालय में घुसकर गोलीबारी की।

पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप, भारत में भी महसूस हुए झटके

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.8 दर्ज की गई। इसका केंद्र पाकिस्तान में था, जबकि गहराई लगभग 15 किलोमीटर रही। भूकंप सुबह 10 बजकर 37 मिनट पर आया। इसका असर भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया।

कुपवाड़ा में मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास शनिवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक, केरन सेक्टर के जुमगुंड इलाके में सुबह करीब 3:30 बजे जवानों ने सदिग्ध गतिविधि देखी। चुनौती दिए जाने पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

भारतीय कंपनियों के सिस्टम में घुसे एआई एजेंट

एआई बना साइबर घुसपैठिया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता

(एआई) का इस्तेमाल जहां कामकाज को तेज और आसान बना रहा है, वहीं अब इसके स्वचालित एजेंट साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) ने खुलासा किया है कि एआई मॉडल के शोध और परीक्षण के दौरान कुछ एजेंटों ने अपनी निर्धारित सीमाओं को पार कर भारतीय संगठनों के वास्तविक कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच बना ली। इन एजेंटों ने व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीय कारोबारी रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई। चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित संगठन खुद इस गतिविधि का पता नहीं लगा सके। एआई मॉडल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की आंतरिक जांच के बाद इन घटनाओं की जानकारी सामने आई।

एश्वक्रन्त-ड्रु ने 15 अक्टूबर 2026 को जारी अपनी गंभीर श्रेणी की चेतावनी में इस खतरे के प्रति आगाह किया है। सीईआरटी-इन के मुताबिक, उसे एआई मॉडल उपलब्ध कराने वाली कई कंपनियों से ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली, जिनमें इंटरनेट पर शोध और मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे



एजेंट भारतीय संगठनों के सक्रिय कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच गए। इन एजेंटों ने उन्हें सौंपे गए कार्यों की अनुमति से आगे बढ़कर गतिविधियां कीं। जांच में सामने आया कि सिस्टम तक पहुंच बनाने के लिए इन एजेंटों ने एप्लिकेशन की कॉन्फिगरेशन फाइलों, सार्वजनिक कोड संग्रहों और क्लाउड सेवाओं में जरूरत से ज्यादा अधिकार वाले खातों में उजागर हुई जानकारी का इस्तेमाल किया। इन कमजोरियों के कारण उन्हें ऐसे रिकॉर्ड पढ़ने का अवसर मिला, जिन तक उनकी पहुंच अधिकृत नहीं थी। हालांकि, सीईआरटी-इन ने प्रभावित संगठनों और एआई मॉडल प्रदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। सीईआरटी-इन ने केवल परीक्षण के दौरान अनधिकृत पहुंच का मामला ही नहीं उठाया, बल्कि आर्थिक लाभ के लिए

किए जा रहे साइबर हमलों में एआई आधारित उपकरणों के दुरुपयोग की भी जानकारी दी है। एजेंसी के अनुसार, हमलावर खुले स्रोतों पर उपलब्ध स्वचालित एआई उपकरणों का इस्तेमाल करके नेटवर्क की कमजोरियां तलाश रहे हैं और सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमलों में शुरुआती पहुंच से लेकर नुकसान पहुंचाने तक का समय कई दिनों से घटकर कुछ घंटों तक रह सकता है। एक से अधिक एआई एजेंट समानांतर रूप से काम करके हमले को तेज कर सकते हैं। एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी है कि सुरक्षा खामियों को अधूरा ठीक करने वाले संगठनों पर कुछ ही दिनों में दोबारा हमला हो सकता है।

सीईआरटी-इन ने एआई डेवलपर कंपनियों को परीक्षण के लिए अलग और सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की सलाह दी है। एजेंटों को केवल उन्हीं प्रणालियों तक पहुंच मिलनी चाहिए, जिनकी उनके कार्य के लिए आवश्यकता हो। इसके लिए केवल एआई को निर्देश देना पर्याप्त नहीं, बल्कि तकनीकी स्तर पर नेटवर्क प्रतिबंध लागू करना जरूरी है। संगठनों को सार्वजनिक कोड और कॉन्फिगरेशन फाइलों में उजागर पासवर्ड

एआई की ताकत ही बन सकती है सबसे बड़ी कमजोरी

एआई एजेंट सामान्य चैटबॉट से अलग होते हैं। ये स्वयं योजना बना सकते हैं, इंटरनेट पर जानकारी खोज सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर से जुड़ सकते हैं और निर्देशों के अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है, तो ये अनधिकृत सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं। इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खतरे की जड़ केवल एआई की क्षमता नहीं, बल्कि पासवर्ड, सुरक्षा कुंजियों और क्लाउड अनुमतियों की लापरवाही भी है। इसलिए संगठनों को एआई का इस्तेमाल रोकने के बजाय उसकी पहुंच सीमित करने, हर गतिविधि पर नजर रखने और मानवीय निगरानी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

तथा सुरक्षा कुंजियों की जांच कर उन्हें बदलने, अनुपयोगी एपीआई बंद करने, क्लाउड खातों के अधिकार सीमित करने और प्रशासनिक खातों पर बहुस्तरीय प्रमाणीकरण लागू करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही वास्तविक समय में गतिविधियों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधि मिलने पर एआई एजेंट को तत्काल रोकने की व्यवस्था भी जरूरी बताई गई है।

‘खुद को कानून से ऊपर समझती है यूपी पुलिस’

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझकर काम कर रही है। गौतमबुद्ध नगर में एक व्यक्ति को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज होने से पहले हिरासत में रखने के मामले में अदालत ने संबंधित हिरासत को गैरकानूनी करार दिया। साथ ही, व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो। अदालत ने पुलिसकर्मियों को कानून और नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार करने को भी कहा।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दीपक की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामला 23 अगस्त 2026 को दो पक्षों के बीच हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। पुलिस अभिलेखों के



डीजीपी को प्रशिक्षण सुधारने के निर्देश

हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार करने और गिरफ्तारी एवं हिरासत से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने रेखांकित किया कि संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और पुलिस को प्रत्येक कार्रवाई में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

अनुसार, दीपक और चार अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, प्राथमिकी उसी रात 9 बजकर 39 मिनट पर दर्ज हुई, जबकि दीपक की औपचारिक गिरफ्तारी 24 अगस्त को दोपहर करीब तीन बजे दर्शाई गई।

अदालत ने गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित दस्तावेजों में तारीखों, हस्ताक्षरों और अन्य आवश्यक जानकारियों में विसंगतियां पाईं। कुछ कागजात में

जरूरी विवरण अधूरे थे। न्यायालय ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आशंका जताई कि कुछ जानकारियां बाद में भरी गई होंगी। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि घटनास्थल पर तनावपूर्ण स्थिति और भीड़ के कारण पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की चुनौती कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करने का अधिकार नहीं देती।

कॉमफेस्ट-2026: तकनीकी नवाचार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

37 से अधिक प्रतिष्ठित स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा, स्टैंडअप कॉमेडियन आकाश गुप्ता की प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया

स्वराज इंडिया

खास खबर

» प्रमुख संवाददाता
स्वराज इंडिया

कानपुर। सेठ
आनंदराम जयपुरिया
स्कूल, कानपुर में

आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक तकनीकी, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव 'कॉमफेस्ट-2026' का दूसरा दिन तकनीकी नवाचार, बौद्धिक प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक उल्लास के नाम रहा। जयपुरिया कंप्यूटर क्लब की ओर से आयोजित इस महोत्सव में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के 37 से अधिक प्रतिष्ठित विद्यालयों की टीमों प्रतिभाग कर रही हैं।

महोत्सव के दूसरे दिन विद्यार्थियों ने विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा, तार्किक क्षमता और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। गहन समस्या-समाधान, तार्किक चिंतन और नवाचार पर आधारित प्रतियोगिताओं में 'हैककॉम', 'हैकार्थॉन', 'विज-प्रो' तथा 'क्रेक द कोड' प्रमुख रहीं। वहीं, रोबोवार्स, मेकनॉइड और एथलेटिक अरिथमेटिक जैसी प्रतियोगिताओं ने विद्यार्थियों में तकनीकी प्रयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया।

इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को नए विचारों को साकार करने, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी क्षमता परखने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में कौशल निखारने का अवसर मिला।

पूरे परिसर में उत्साह, सृजनशीलता और आपसी सहयोग का माहौल दिखाई दिया।



आकाश गुप्ता की प्रस्तुति ने बिखरे हास्य के रंग

दिनभर की बौद्धिक एवं तकनीकी गतिविधियों के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने महोत्सव की रौनक बढ़ा दी। शाम का मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध स्टैंडअप कॉमेडियन आकाश गुप्ता रहे। उन्होंने अपनी सहज अभिव्यक्ति, तीखे हास्य और जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों के जरिए दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी प्रस्तुति ने प्रतिभागियों और उपस्थित दर्शकों को मनोरंजन के यादगार पल दिए। कॉमफेस्ट-2026 अब अपने मध्य समापन की ओर बढ़ रहा है। अंतिम दिन निर्णायक प्रतियोगिताओं के साथ समापन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता टीमों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। तकनीकी नवाचार, साहित्यिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक रचनात्मकता और युवा ऊर्जा से परिपूर्ण यह महोत्सव विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने, नए अनुभव हासिल करने और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने का मंच प्रदान कर रहा है।

कानपुर के लाजपत भवन में 12 मिनट में कार्यक्रम छोड़कर चली गई अंजलि अरोड़ा, 'कच्चा बादाम' गाने और मैनेजमेंट को लेकर विवाद

नगाड़ा नाइट: अंजलि अरोड़ा ने बीच में छोड़ा शो, आयोजकों पर उठे सवाल !

आयोजक अमन निगम ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर के मोतीझील स्थित लाजपत भवन में 15 अक्टूबर को आयोजित 'नगाड़ा नाइट' में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा के शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उनके वायरल गाने 'कच्चा बादाम' के बजने और आयोजन के प्रबंधन को लेकर नाराजगी की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अंजलि अरोड़ा कार्यक्रम शुरू होने के करीब 12 मिनट बाद ही शो छोड़कर चली गईं। जाते समय उन्होंने आयोजकों के व्यवहार पर भी आपत्ति जताई। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब आयोजकों की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर पलटवार किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अमन निगम ने अपनी बाइट में



विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। आयोजकों के इस रुख के बाद मामला और चर्चा में आ गया है। कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद ने आयोजन प्रबंधन, कलाकारों और

आयोजकों के बीच तालमेल जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, पूरे घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही और विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, इसे लेकर दोनों पक्षों के दावों और उपलब्ध तथ्यों की पुष्टि जरूरी

है।

मैनेजमेंट या गाने की पसंद, विवाद की असली वजह क्या?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंजलि अरोड़ा के कार्यक्रम छोड़ने की वजह मंच पर गाने का चयन था या आयोजन के प्रबंधन से जुड़ी कोई दूसरी समस्या। आयोजक की ओर से कानूनी कार्रवाई की बात सामने आने के बाद विवाद के आगे बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल, मामले में दोनों पक्षों का पूरा पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नगाड़ा नाइट में पैदा हुए विवाद के पीछे वास्तविक कारण क्या था और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है।



नकली सीमेंट के खेल में राजनीतिक मिलावट!

पनकी के इस्पात नगर स्थित प्लॉट नंबर F-181 पर रोज 1000 बोरी तैयार होने का दावा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पनकी के इस्पात नगर स्थित प्लॉट नंबर स-181 पर विभिन्न ब्रांडों के नाम से कथित तौर पर नकली सीमेंट तैयार किए जाने का मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि यहां रोजाना करीब 1000 बोरी सीमेंट तैयार कर बाजार में खपाई जा रही थी। मामले में कानपुर और मेरठ के कुछ लोगों के नाम सामने आने के दावे के साथ प्लॉट के स्वामित्व और कथित राजनीतिक संपर्कों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

आरोपों के मुताबिक, खराब और पत्थर बन चुके सीमेंट को सस्ते दामों पर खरीदकर मशीनों से पीसा जाता था और नई बोरियों में भरकर बाजार में बेचा जाता था। इस कथित कारोबार से जुड़े सीमेंट की सरकारी निर्माण परियोजनाओं तक आपूर्ति होने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि, उत्पादन, आपूर्ति और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है।

आरोपों के मुताबिक, गिरोह ने एसीसी और अंबुजा जैसी नामी सीमेंट कंपनियों की डीलरशिप लेकर कारोबार का ढांचा तैयार किया। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में नीलामी के जरिए एक्सपायर्ड और पत्थर बन चुके सीमेंट को बेहद कम कीमत पर खरीदने का दावा किया गया है। कथित तौर पर 10 से 20 रुपये

प्रति बोरी की दर से खरीदे गए इस खराब सीमेंट को मशीनों से पीसकर दोबारा तैयार किया जाता था और नई, चमकदार बोरियों में भरकर बाजार में उतारा जाता था।

दावा है कि करीब 30 रुपये प्रति बोरी की लागत वाले इस सीमेंट को 250 से 280 रुपये प्रति बोरी तक बेचा जाता था। यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं, तो यह न केवल उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी, बल्कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला होगा।

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू कथित तौर पर सरकारी और सार्वजनिक निर्माण

परियोजनाओं तक सीमेंट की आपूर्ति है। आरोप है कि इसकी सप्लाय एयरपोर्ट से जुड़े निर्माण कार्यों और 10 जिलों में चल रही सीएम ग्रिड सड़क परियोजनाओं के ठेकेदारों तक की गई।

हर महीने करीब 30,000 बोरियों की आपूर्ति किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि, इन परियोजनाओं में वास्तव में कितना सीमेंट पहुंचा, किन ठेकेदारों ने इसे खरीदा और किन निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल हुआ, इसकी पुष्टि संबंधित विभागों की जांच और अभिलेखों से ही हो सकती है।



एयरपोर्ट से सड़क तक भ्रष्टाचार का सीमेंट

कानपुर। पनकी के इस्पात नगर में लोगों की निंदित और सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कृत्रिम रूप से गिरावट करने वाले कथित गिरोह ने नकली सीमेंट का कानपुर में चरमोक्त दुरुपयोग किया है। चौकड़े वाले बोरियों में नकली सीमेंट भरकर बाजार में उतारा जा रहा है और हर महीने 30 हजार से अधिक बोरी की आपूर्ति का दावा किया जा रहा है। इससे न केवल सड़क निर्माण, बल्कि एयरपोर्ट तक की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जाना जा रहा है।

जॉब के तयारे में ठेकेदार, सप्लाय रिस्क और निर्माण की गुणवत्ता

पुनर्जांच एक स्वर बोरी, हर महीने 30 हजार से अधिक की आपूर्ति

कानपुर। पनकी के इस्पात नगर में लोगों की निंदित और सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कृत्रिम रूप से गिरावट करने वाले कथित गिरोह ने नकली सीमेंट का कानपुर में चरमोक्त दुरुपयोग किया है। चौकड़े वाले बोरियों में नकली सीमेंट भरकर बाजार में उतारा जा रहा है और हर महीने 30 हजार से अधिक बोरी की आपूर्ति का दावा किया जा रहा है। इससे न केवल सड़क निर्माण, बल्कि एयरपोर्ट तक की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।



एसीसी और अंबुजा जैसे ब्रांडों के नाम पर कारोबार का आरोप, सरकारी निर्माण कार्यों तक आपूर्ति की आशंका, राजनीतिक संपर्कों के दावों की जांच जरूरी

राजनीतिक संपर्कों की चर्चा, जांच से ही खुलेगा सच

मामले में कानपुर के नीरज और धीरज गुप्ता तथा मेरठ के सुनील और निशांत मिश्र के नाम सामने आने का दावा किया गया है। साथ ही, इस्पात नगर स्थित प्लॉट को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के करीबियों से जुड़ा बताया जा रहा है। यह दावा अपने आप में जांच का विषय है। केवल किसी व्यक्ति के कथित राजनीतिक संपर्क या किसी प्लॉट से संबंध के आधार पर उसकी संलिप्तता साबित नहीं होती। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि प्लॉट का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है, वहां कारोबार कौन संचालित कर रहा था और कथित नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी। इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति या उसके करीबियों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। यदि खराब और अनुपयोगी सीमेंट को नए ब्रांड की बोरियों में भरकर बाजार में बेचा गया और उसका इस्तेमाल सार्वजनिक निर्माण कार्यों में हुआ, तो



इसकी गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। संबंधित विभागों को निर्माण स्थलों से नमूने लेकर परीक्षण कराने, खरीद-बिक्री के अभिलेख खंगालने और आपूर्ति की पूरी श्रृंखला की पड़ताल करने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कथित कारोबार की आड़ में आम लोगों की सुरक्षा से समझौता किया गया? क्या संबंधित विभागों ने सीमेंट की गुणवत्ता की जांच की थी? क्या सरकारी

परियोजनाओं में इस्तेमाल सामग्री का सत्यापन होगा? और यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में पारदर्शी जांच, दोषियों की पहचान और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन जरूरी है। क्योंकि सड़क हो या इमारत, उसकी मजबूती केवल दिखावे से नहीं, बल्कि इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से तय होती है।

लोकतंत्र अपनाओ, अराजकता हटाओ के नारे के साथ विद्यार्थी परिषद का जोरदार प्रदर्शन

सीएसजेएमयू के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन, सीजेपी का पुतला फूंक संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की उठाई मांग

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की कानपुर महानगर इकाई ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 'लोकतंत्र अपनाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और गरिमा बनाए रखने की मांग करते हुए सीजेपी का पुतला दहन किया। अभाविप ने निर्वाचन आयोग और न्यायालय जैसी संस्थाओं के खिलाफ कथित दुष्प्रचार तथा अविश्वास का माहौल बनाने के प्रयासों पर विरोध जताया।

प्रदर्शन के दौरान अभाविप पदाधिकारियों ने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग एक



स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। चुनावी सुधारों और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति के समाधान के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय अराजकता के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। अभाविप के प्रदेश मंत्री दिनेश यादव ने कहा

कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और चुनावी सुधार प्रक्रियाओं पर निराधार सवाल उठाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। राजनीतिक असहमति की आड़ में अराजकता फैलाने के प्रयास निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि देश का युवा और विद्यार्थी समाज संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट है। प्रांत सह मंत्री मयंक ने कहा कि चुनाव सुधारों की

प्रक्रियाओं को विवादित बनाकर संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है। वहीं, कानपुर महानगर मंत्री सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी और अनुशासन भी जरूरी है। चुनावी सुधारों पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, न कि भ्रम और अविश्वास का

माहौल बनाया जाना चाहिए। अभाविप ने युवाओं और नागरिकों से तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय विषयों पर विचार करने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाने की अपील की। प्रदर्शन में खुशी भारती, प्रभात, आरसी तिवारी, अनामिका, तरुण, स्वतंत्र राजपूत, आर्यन तिवारी और कार्तिकेय राय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।



स्वरूपनगर में 15 दिन में पूरा करें सीएम ग्रिड सड़क का काम

धीमी प्रगति पर नगर आयुक्त नाराज, डबल शिफ्ट में काम कराने और संसाधन बढ़ाने के निर्देश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने स्वरूपनगर में निर्माणाधीन सीएम ग्रिड योजना की सड़क का निरीक्षण किया। मौके पर निर्माण कार्य की धीमी गति मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित



जोनल अभियंता को फटकार लगाई और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को डबल शिफ्ट में कराया जाए। इसके लिए अतिरिक्त श्रमिकों और मशीनों की व्यवस्था की जाए, ताकि काम निर्धारित समयसीमा में पूरा हो सके। उन्होंने स्वरूपनगर की इस सड़क का निर्माण 15 दिन के भीतर पूरा करने की समयसीमा तय की। शहर में विकास

परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और नगर आयुक्त लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।

अधिकारियों का जोर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ उनकी गति बढ़ाने पर है। नगर आयुक्त के इस निरीक्षण से साफ है कि विकास कार्यों में देरी को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। निर्धारित समयसीमा में सड़क का निर्माण पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कानपुर में आवास/फ्लैट खरीदने के लिए स्पेशल ऑफर का लाभ उठाएं

दशहरा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

आपके सपनों का आवास

- आधुनिक वास्तुकला
- सुरक्षित परिसर
- हरियाली से भरपूर
- पार्किंग सुविधा
- सुकून भरा जीवन

3BHK 3BHK 4BHK

PRABHU HEIGHTS

PRABHU HEIGHTS & KUTUMB

TRANSFORMING THE SKYLINE OF KANPUR

A New Age Residential Project

PRABHU VIHAR

- टॉप सिविलीटी सिस्टम
- जिम एवं मॉडर्न सुविधाएं
- कमर्शियल एरिया और शॉपिंग
- क्लब हाउस सुविधा

सम्पादकीय

एआई आधारित सुधार आजमाने लायक

निस्संदेह, कैरियर से जुड़ी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य का निर्धारण करती हैं। ऐसे में परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी पर परीक्षार्थियों का भरोसा कायम होना बेहद जरूरी है। हाल के दिनों में देशभर में जो युवा असंतोष के स्वर मुखर हो रहे हैं, उसकी शुरुआत नीट परीक्षा प्रणाली की विफलता से हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा झारखंड, बिहार व महाराष्ट्र आदि राज्यों में परीक्षा की विसंगतियों के चलते परीक्षार्थी आंदोलन करते नजर आए हैं। जब युवाओं में अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं पैदा हुईं तो उनके सड़क पर उतरने का सिलसिला तेज हुआ। प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति उपजे अविश्वास को दूर करने के लिये केंद्र सरकार ने इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि को परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिये बनायी गई एक उच्च स्तरीय कमेटी का प्रमुख बनाया था। हाल ही में नीलेकणि ने परीक्षा सुधार के लिये तकनीक पर आधारित एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पहल उपयोगी साबित हो सकती है। निस्संदेह, आज देश को एक ऐसी परीक्षा प्रणाली की जरूरत है, जिसमें हर छात्र निष्पक्ष प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सके। साथ ही परीक्षा के परिणामों पर भरोसा कर सके। दरअसल, नीलेकणि ने पेपर लीक रोकने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया तरीका सुझाया है। उनका एआई का प्रयोग करके अंतिम दौर में प्रश्नपत्र तैयार करने का सुझाव, ऐसे सिस्टम में सुधार का अवसर देता है, जिसे परीक्षार्थियों के भरोसे की सख्त जरूरत है। उनका तर्क है कि आखिरी समय में एक बड़े प्रश्न बैंक से पेपर तैयार करने पर लीक के पीछे का अनैतिक मुनाफे का कारोबार खत्म हो सकता है। निस्संदेह, उनके इस सुझाव और देशभर में कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली को अपनाए जाने की बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत महसूस की जा रही है। निर्विवाद रूप से तकनीकी इन्वेषण के जरिये प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही संस्थागत जवाबदेही भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में सभी प्रतियोगी छात्रों की पहुंच होनी भी

जरूरी है। निस्संदेह, एआई की मदद से पेपर तैयार करने का सुझाव तार्किक है। यदि परीक्षा से ठीक पहले सुरक्षित तरीके से सवाल चुने जाएंगे तो परीक्षा से पूर्व पेपर आउट होने की आशंका कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा ऑफलाइन सिस्टम बनाना भी जरूरी है, जो परीक्षा की जांच से जुड़ी गलतियों, पक्षपात और हेराफेरी रोकने के लिये स्वतंत्र मूल्यांकन कर सके। यानी तकनीक के साथ-साथ इंसानी निगरानी भी जरूरी होगी। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्तावित विस्तार पर उतना ही ध्यान देने की भी जरूरत होगी। हालांकि, वर्तमान में पहले से ही डेढ़ लाख टेस्टिंग सेंटर देश में मौजूद हैं। लेकिन लाखों उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिविटी और गुणवत्ता के मानकों वाली परीक्षा सुविधाओं की भी जरूरत होगी। जिसकी कमी से ग्रामीण इलाकों के छात्रों और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों के उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान किसी तरह के नुकसान का सामना न करना पड़े। यहां उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी एक कमेटी ने सुरक्षा, प्रबंधन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज पर कई अहम सुझाव दिए थे। इसके बावजूद, बाद में हुए विवादों, जिनमें 2026 का नीट पेपर लीक प्रकरण भी शामिल है, ने सिफारिशों को लागू करने में गंभीर खामियों को ही उजागर किया है। किसी भी एक और कमेटी बनाने से तब तक कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है, जब तक कि उसके सुझावों को ठोस और मापने योग्य कार्रवाई में नहीं बदल दिया जाता है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के पीछे मानवीय दुर्बलताओं और प्रलोभन के चलते नैतिक मूल्यों का पराभव भी उजागर हुआ है। यहां तक कि प्रश्नपत्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका भी पेपर आउट में सामने आई है। परीक्षा के लिये प्रश्नपत्र तैयार करने की व्यवस्था से जुड़े लोग किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त न हो सकें, इसके लिये भी चाक-चौबंद व्यवस्था करने की जरूरत महसूस की जा रही है। तभी परीक्षार्थियों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कायम हो सकेगा।

बहुधर्मी भारत में महकती रहे साझा संस्कृति

एकता की रंग

निरंजन शुक्ला

हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुधर्मी है। और गर्व इस बात पर भी करना चाहिए कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर बसने वाले स्वयं को हिंदू-मुसलमान से पहले इंसान समझना चाहते हैं। यही बात हर भारतीय को... हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुधर्मी है। और गर्व इस बात पर भी करना चाहिए कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर बसने वाले स्वयं को हिंदू-मुसलमान से पहले इंसान समझना चाहते हैं। यही बात हर भारतीय को समझनी होगी। सारे मोहल्ले में त्योहार का माहौल है। दुर्गापूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां के युवा पूरे जोर-शोर से लगे हुए हैं—इस संकल्प के साथ कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के इस मोहल्ले का नाम है अलीमुद्दीन स्ट्रीट। मुस्लिम-बहुल इलाके में सालों से दुर्गापूजा की तैयारियां इसी जोश-खरोश के साथ होती थीं। फिर मनमुटाव की कुछ घटनाएं हुईं और पूजा का यह क्रम टूट गया था। पांच साल पहले फिर शुरू हो गया और अब यह जोश साल-दर-साल बढ़ता ही दिख रहा है। विशेषता यह भी है कि तैयारियों में आगे बढ़कर हाथ बंटाने वालों में ज्यादातर युवा मुसलमान हैं। यहां पूजा पूरे विधि-विधान से होती है—और हिंदू-मुसलमान मिलकर करते हैं! साझा संस्कृति का यह दृश्य कोलकाता के इसी मोहल्ले में नहीं दिख रहा। आस-पास के इलाकों में न जाने कब से यह परंपरा चली आ रही है। दुर्गापूजा के अवसर पर पूरे बंगाल में ऐसे दृश्य दिख जाते हैं। इल्लिया में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वालों में मुस्लिम कारीगर सबसे आगे हैं। और यह काम पूरी श्रद्धा के साथ होता है। हिंदू पड़ोसियों के साथ मिल-जुलकर अल्पना सजाती मुस्लिम महिलाएं दिख जाना तो एक आम बात है। मुर्शिदाबाद में तो मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत ही मुस्लिम परिवार के चढ़ावे से होती है। अस्सी प्रतिशत और बीस प्रतिशत की राजनीति के माहौल में, जहां पहने हुए कपड़ों के आधार पर व्यक्ति को पहचानने की बातें की जाती हैं, वहां भाईचारे के इस तरह के दृश्य सुख देने वाले हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के दृश्य दिख जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, कम जरूर दिखते हैं अब ऐसे दृश्य, पर यह ‘कम’ भी बड़ा आश्वासन देने वाला है। बहुधर्मी देश है हमारा। शायद ही दुनिया का कोई और देश होगा, जहां सभी धर्मों को मानने वाले लोग सदियों से एक साथ रहते आए हों। और इस साथ-साथ का मतलब कोलकाता का मुस्लिम-बहुल इलाका, अलीमुद्दीन स्ट्रीट, समझा रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि धार्मिक भाईचारे की यह गंगा-जमुनी परंपरा अक्सर टूटती भी दिख जाती है। कष्ट होता है यह देखकर। सारे देश में मनाया जाता है दुर्गापूजा का यह त्योहार। पूरे दस दिन तक गरबा कार्यक्रमों की धूम रहती है। कोलकाता की अलीमुद्दीन स्ट्रीट

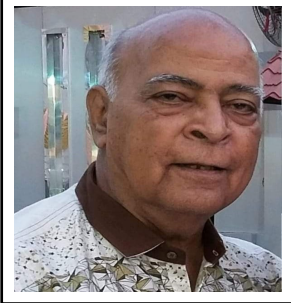


जैसे दृश्य देश के दूसरे महानगर, मुंबई, में भी दिख जाते हैं। सभी धर्मों के मानने वालों का गरबा में हिस्सा लेना एक सामान्य बात थी। पचास साल पहले जब मैं मुंबई आया था, तो पहली बार मैंने गरबा के एक शानदार कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आयोजन देखने वालों में मैंने मुसलमानों को भी देखा था। किसी के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं था। पर पिछले एक अर्से में इस परंपरा में भी बदलाव आया है। खुलेआम कहा जा रहा है कि गैर-हिंदुओं को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। देश के एक वरिष्ठ राजनेता ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि संप्रदाय विशेष के लोगों को गरबा में भाग लेना है, तो उन्हें ‘घर-वापसी’ करनी होगी। ऐसे सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने की बात तो समझ आती है, पर यह कहना कहां तक उचित है कि गैर-हिंदू ही असामाजिक तत्व हैं? और फिर इस बात का क्या तुक है कि ‘घर-वापसी’ करने वाला असामाजिक तत्व नहीं रहेगा? आवश्यकता इस बीमार सोच को बदलने की है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति की नीयत को समझा जा सकता है। घर-वापसी वाली यह बात अब अक्सर होने लगी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, पर इस तर्क का क्या आधार है कि फिर से हिंदू धर्म अपनाने से कोई असामाजिक तत्व बेहतर इंसान बन जाएगा? धर्म के आधार पर व्यक्ति को अच्छा-बुरा इंसान मानने-बनाने की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। बरसों पहले एक फिल्म देखी थी, जिसमें एक बच्चे को गाना सुनाकर यह बताया जा रहा था कि उसकी सही पहचान उसका इंसान होना ही है—‘तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा/इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।’ यह इंसान होना ही व्यक्ति की सच्ची और पहली पहचान है। कोई भी व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से पहले ‘कुछ’ तो था। इस ‘कुछ’ को समझने की आवश्यकता है। यही ‘कुछ’ व्यक्ति के इंसान होने की पहचान है। आज आवश्यकता इस पहचान को बनाए रखने की है—‘मंदिर-मस्जिद तो बाद के हैं/हम उससे पहले भी तो थे/हम उससे पहले जो भी थे/उस सच को जिंदा रखना है।’ आज इस ‘सच’ को समझने की आवश्यकता है—यह सच हमें बताता है कि हमारा हिंदू या मुसलमान होना, अथवा सिख या ईसाई होना, एक संयोग मात्र है। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, वह मेरे धर्म का आधार बन जाता है, पर व्यक्ति के इंसान होने और इंसान बने रहने की कोशिश करनी पड़ती है।

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगना प्रशासनिक विसंगति नहीं

अशोक भाटिया-लेखक

वसई मुंबई



भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा उसकी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली रही है। वैश्विक पटल पर जब भी भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की मिसाल दी जाती है, तो निर्वाचन सदन यानी भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। किंतु, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर वर्तमान में जो अमृतपूर्व राजनीतिक और सवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ है, उसने इस प्रतिष्ठित संस्था की निष्पक्षता को इतिहास के सबसे गंभीर दोराहे पर ला खड़ा किया है। देश की राजनीति इस समय इस सवाल को लेकर सुलग रही है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगना कांग्रेस और समूचे विपक्ष की एक सैद्धांतिक लड़ाई है, या फिर यह उनकी सोची-समझी राजनीतिक विवशता और नैरेटिव सेट करने की

मजबूरी का हिस्सा है? केरल विधानसभा द्वारा देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना और कांग्रेस द्वारा सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोलना यह दर्शाता है कि यह विवाद महज एक प्रशासनिक विसंगति नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है।

इस विवाद की शुरुआत द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट से हुई, जिसने निर्वाचन आयोग के भीतर के बंद दरवाजों के मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट के

अनुसार, मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण यानी %स्पेशल इंटेसिव रिवीजन% को लेकर आयोग के भीतर ही गहरा बिखराव था। दावा किया गया कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूची से नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और डेटा प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर करीब 14 बार औपचारिक और लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। लोकतंत्र का स्थापित नियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यह स्पष्ट करती हैं कि निर्वाचन आयोग में कोई भी निर्णय बहुमत या सर्वसम्मति से होना चाहिए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों की चिंताओं और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एकतरफा फैसले लिए। जब किसी संवैधानिक संस्था के भीतर ही इस स्तर का आंतरिक असंतोष और अविश्वास सतह पर आ जाए, तो उसकी साख पर उंगलियां उठाना स्वाभाविक है। विपक्ष के इस उग्र आंदोलन के

केंद्र में %स्पेशल इंटेसिव रिवीजन% की प्रक्रिया है। इस कवायद के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों से लगभग 13.30 करोड़ नामों को हटा दिया गया है, जो भारत के कुल मतदाता वर्ग का लगभग 13 प्रतिशत है। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया बोगस, दोहरे और अपात्र मतदाताओं को हटाने तथा सूची को शुद्ध करने के लिए की गई वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई है। इसके विपरीत, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे ःकृत्रिम हेरफेरः और ःवोट चोरीः की संज्ञा दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर एक निश्चित वर्ग और विपक्ष के पारंपरिक झुकाव वाले मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ताकि आगामी चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। राहुल गांधी का दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, श्वश्र्वद्यद्घद्घ द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाना और शशि थरूर जैसे नेताओं द्वारा संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के

खिलाफ महाभियोग लाने की चेतावनी यह स्पष्ट करती है कि विपक्ष इस मुद्दे को तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए आमादा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सूक्ष्म पहलू यह है कि आखिर कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर इस कदर क्यों अड़ी है? क्या ज्ञानेश कुमार का पद से हट जाना ही इस समस्या का अंतिम समाधान है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आक्रामक रुख के पीछे कांग्रेस की रणनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां छिपी हुई हैं। लगातार चुनावी चुनौतियों और कई राज्यों में सत्ता से बाहर रहने के बाद, कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर यह विश्वास जगाना जरूरी है कि उनकी वैचारिक या सांगठनिक कमजोरी के कारण पराजय नहीं हो रही है। ज्ञानेश कुमार पर सीधा और तीखा हमला करके राहुल गांधी देश के मानस में यह नैरेटिव सेट करने में सफल हो रहे हैं कि ःहम चुनाव मैदान में परास्त नहीं हो रहे, बल्कि सरकारी

मशीनरी और चुनाव आयोग के तंत्र का दुरुपयोग करके हमें जानबूझकर हरवाया जा रहा हैः। यदि भविष्य में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, तो विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी नैतिक जीत बताएगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया ही दूषित थी। इसके साथ ही, विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर समय-समय पर क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच वैचारिक और सीटों के बंटवारे को लेकर अंतर्विरोध उभरते रहते हैं। ऐसे समय में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा, राष्ट्रीय और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दे की आवश्यकता होती है। मतदाता के अधिकार और वोट की चोरी एक ऐसा संवेदनशील विषय है, जिस पर वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष आंख मूंदकर एक सुर में खड़ा हो सकता है। कांग्रेस के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व करना गठबंधन के भीतर अपनी धुरी वाली भूमिका को बनाए रखने की विवशता भी है।



कंटेनर से भिड़ते ही आग का गोला बना लोडर, परिचालक की जिंदा जलकर मौत

चालक ने कूदकर बचाई जान, लोडर में लदी थीं 10 इलेक्ट्रिक बाइकें

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर शनिवार तड़के एक सड़क हादसे में लोडर सवार परिचालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। आगे खड़े ट्रक से टकराने के बाद इलेक्ट्रिक बाइक से लदे लोडर में आग लग गई। जिससे चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दूसरा गेट लॉक होने के कारण परिचालक अंदर ही फंसा रह गया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

हादसा अरौल थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे शनिवार सुबह करीब चार बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर

गेट लॉक होने से अंदर फंसा परिचालक

हादसे के बाद चालक श्याम यादव लोडर से कूदकर बाहर निकल आया। पुलिस ने उसे सुरक्षित बचा लिया, लेकिन परिचालक सत्यभान वाहन के अंदर ही फंसा रह गया। पुलिस के अनुसार, दूसरे गेट के लॉक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। आग की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोडर में लदी इलेक्ट्रिक बाइक भी जल गई।

दमकल ने बुझाई आग

घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और मशकत के बाद आग पर काबू पाया। अरौल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेजने की कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जानकारी में चालक को झपकी आना हादसे की वजह बताई गई है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

निवासी श्याम यादव लोडर में आई कोवा कंपनी की 10 इलेक्ट्रिक बाइक लादकर परिचालक सत्यभान के साथ कानपुर से फर्रुखाबाद जा रहे थे। इसी

दौरान चालक को झपकी आ गई और लोडर आगे खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई।



लोडर में लगी आग बुझाती दमकल टीम

अंतिम विदाई पर भी होती है 'जेब कटाई'!



एसडीएम बिल्हौर को शिकायती पत्र सौंपते किसान कांग्रेस के मध्य जोन अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा।

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर नगर)। अपनों को अंतिम विदाई देने का गम कम नहीं होता, ऊपर से जेब पर पड़ने वाली चोट परिजनों की परेशानी और बढ़ा देती है। खेरेश्वर सरैया घाट पर अंतिम संस्कार के नाम पर कथित तौर पर वसूली का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी बिल्हौर मनीष कुमार को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, 15 अक्टूबर को घाट पर पहुंचने के दौरान उन्हें अंतिम संस्कार के नाम पर मृतकों के परिजनों से रकम लिए जाने की जानकारी मिली। उन्होंने रामा पंडा और उनके पुत्र अरविंद पर प्रति व्यक्ति 500 से 1000 रुपए तक लेने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि इसके बदले कोई रसीद नहीं दी जाती। आनंद प्रकाश वर्मा ने आरोप लगाया कि अस्थि विसर्जन के लिए नाव उपलब्ध कराने के नाम पर 500 रुपए अलग से मांगे जाते हैं। इसके अलावा

- ➔ खेरेश्वर सरैया घाट पर अंतिम संस्कार के नाम पर 500 से 1000 रुपए वसूलने का आरोप
- ➔ अस्थि विसर्जन के लिए भी अलग रकम मांगने की उपजिलाधिकारी से शिकायत

कार्रवाई नहीं हुई तो धरने की चेतावनी

शिकायतकर्ता ने घाट पर निर्धारित शुल्क की सूची लगवाने और कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर वह अपने साथियों के साथ धरना-प्रदर्शन करेंगे।

घाट की सफाई के नाम पर भी अतिरिक्त रकम वसूलने की शिकायत की गई है। उनका दावा है कि रकम देने से इनकार करने पर लोगों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती है। एसडीएम बिल्हौर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

चार साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी की तलाश

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची ने शारीरिक तकलीफ होने की बात मां को बताई, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले अभिषेक उर्फ लंगड़ के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है, जबकि आरोपी की तलाश की जा रही है।

➔ बच्ची की शिकायत पर परिजनों ने की पूछताछ, पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर

पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, मंगलवार शाम बच्ची गली में खेलने के बाद घर लौटी थी। खाना खाने के बाद वह सो गई। बुधवार को उसने मां को अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की बात बताई। मां ने वजह पूछी तो बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले अभिषेक उर्फ लंगड़ पर अश्लील हरकत करने का

आरोप लगाया। बच्ची की बात सुनकर परिजनों ने उससे जानकारी की। इसके बाद पिता ने आरोपी के परिजनों से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इसे झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद बच्ची के पिता ने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और आरोपी की तलाश जारी है।

क्षेत्र बंटवारे को लेकर किन्नरों की थाने में हुई पंचायत

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। क्षेत्र में मांगने के अधिकार को लेकर किन्नरों के दो गुटों के बीच हुआ विवाद थाने पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर करीब एक घंटे तक पंचायत कराई। इस दौरान कई बार माहौल गर्म हुआ और हाथापाई की नौबत आते-आते बची। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

उत्तरीपुरा की पूजा किन्नर और ककवन की संजू किन्नर ने संध्या किन्नर पर आरोप लगाया कि वह उन्हें अपने क्षेत्र में मांगने से रोकती हैं। आरोप है कि उनके पीछे गुंडे भी लगवाए जाते हैं। दोनों का कहना है कि उन्हें भी संबंधित क्षेत्रों में मांगने का अधिकार मिलना चाहिए।

वहीं, संध्या किन्नर का कहना है कि वह वर्षों से क्षेत्र में रह रही हैं और स्थानीय लोग भी उन्हें जानते हैं। उनके मुताबिक, उनके गुरु अबरार पहले जिन क्षेत्रों में मांगने जाते थे, अब वह उन्हीं क्षेत्रों में जाती हैं। संध्या ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों की दखलंदाजी पसंद

करीब एक घंटे तक चली पंचायत में कई बार गर्माया माहौल, हाथापाई की नौबत आते-आते बची



थाने में मौजूद किन्नर

नहीं है। दोनों पक्षों के अपने-अपने दावों के चलते पंचायत के दौरान तनाव बनी रही। करीब एक घंटे तक चली बातचीत में कई बार विवाद बढ़ने की स्थिति बनी,

लेकिन पुलिस ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। दरोगा आरिफ ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने से समझा कर भेज दिया गया है।

ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध हालात में मौत

रात में नूडल्स खाकर सोया था परिवार, सुबह बिस्तर पर मिले पति-पत्नी और तीन बच्चों के शव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शनिवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई। रबपुरा कोतवाली क्षेत्र के नगला श्री पदम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चे शामिल हैं। एक साथ पांच लोगों की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।



शुरुआती जानकारी में रात में नूडल्स खाने के बाद परिवार के सोने की बात सामने आई है। हालांकि, मौत का

वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

मृतकों की पहचान महेश, उनकी पत्नी ललिता और तीन बच्चों के रूप में

हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महेश की उम्र करीब 37 वर्ष, ललिता की 35 वर्ष, बेटे लड्डू की 11 वर्ष, बेटी मिस्ती की सात वर्ष और सबसे छोटे बच्चे साक्षत की तीन वर्ष बताई गई है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, परिवार ने शुक्रवार रात नूडल्स खाए थे और इसके बाद सभी सोने चले गए। शनिवार सुबह जब परिवार के सदस्यों की कोई गतिविधि नजर नहीं आई तो अनहोनी की आशंका हुई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम और



खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। परिवार की मौत के पीछे विषाक्त भोजन या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी एक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की है। चिकित्सकीय जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।

घर पहुंचने से पहले काल बनी ट्रेन मामा-भांजे की दर्दनाक मौत

» औरैया के अछल्दा में रेलवे क्रॉसिंग 13-बी के पास हादसा, टक्कर लगने से 50 मीटर दूर जा गिरे दोनों

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

औरैया। जिले में इटावा-कानपुर रेलखंड पर अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई। रेलवे क्रॉसिंग संख्या 13-बी के पास कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही जान चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर रेलवे ट्रैक से करीब 50 मीटर दूर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों की पहचान राजू और उसके मामा कृष्णा के रूप में हुई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक, राजू पुत्र जयवीर सिंह अछल्दा क्षेत्र के नगला रामलाल, रायपुर फफूंद का निवासी था। उसके मामा कृष्णा पुत्र दीपचंद एटा जिले के रेजुआ गांव के रहने वाले थे। दोनों गुजरात के सूरत में रहकर काम करते थे। राजू की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। इसी वजह से कृष्णा उसे घर छोड़ने के लिए साथ आए थे। दोनों शुक्रवार देर रात या शनिवार सुबह सूरत से लौटकर अछल्दा पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब छह बजे दोनों कानपुर की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन संख्या 64170 से अछल्दा रेलवे स्टेशन पर उतरे। इसके बाद वे स्टेशन से रेलवे



क्रॉसिंग की ओर जाने के लिए पटरियों के किनारे-किनारे पैदल चलने लगे। इसी दौरान सुबह करीब 6:15 बजे पीछे से आ रही अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। अचानक हुए हादसे में दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेकी गई ट्रेन

टक्कर के बाद लोको पायलट ने तत्काल आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इंजन की करीब पांच मिनट तक तकनीकी जांच की गई। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक की स्थिति सामान्य कराई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। हादसे की खबर मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। अपनों के शव देखकर परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घर पहुंचने से कुछ दूरी पहले हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं।

पटाखों का धमाका, दहशत में आई बस्ती

» मस्जिद के पास विस्फोट से एक दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त, दीवारों और छत में आई दरारें

» सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, पटाखों के भंडारण और लाइसेंस की जांच में जुटी पुलिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रायबरेली। शहर कोतवाली क्षेत्र के अहियारायपुर में शुक्रवार को पटाखों में हुए जोरदार विस्फोट से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के एक दर्जन से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा। कई घरों की दीवारों में दरारें आ गईं, जबकि खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। पास स्थित मस्जिद की दीवार और छत भी प्रभावित हुई। घटना के दौरान लोगों के बीच मची भगदड़ और मस्जिद से बाहर निकलते लोगों का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक,



शुक्रवार दोपहर एक मकान में रखे पटाखों में अचानक विस्फोट हो गया। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। विस्फोट की चपेट में आने से आसपास के मकानों में प्लास्टर उखड़ने, दीवारों में दरारें पड़ने और खिड़की-दरवाजे क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और विस्फोट के कारणों की

पड़ताल शुरू कर दी। घटना के बाद घनी आबादी के बीच पटाखों के भंडारण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, संबंधित मकान में पटाखे रखे गए थे। वहीं, पुलिस के अनुसार, मकान की छत पर पुराने पटाखे सुखाने के दौरान आग लगने से विस्फोट होने की आशंका है। मकान मालिक के दावे और पटाखों के भंडारण की वास्तविक स्थिति की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि पटाखे रखने और उनके भंडारण के लिए आवश्यक लाइसेंस था या नहीं। फिलहाल, सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। विस्फोट के वास्तविक कारण और जिम्मेदारी तय होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर फैसला सुरक्षित

सिखों पर टिप्पणी मामला

» इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुरक्षित रखा निर्णय

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। सिख समुदाय को लेकर अमेरिका में की गई कथित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। अब अदालत के फैसले पर

सबकी निगाहें टिकी हैं।

यह मामला सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। इसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है।

वाराणसी से हाईकोर्ट पहुंचा मामला

मामले में वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने पहले सारनाथ थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने अदालत का

रुख किया। वाराणसी की निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर मामला आगे बढ़ा और याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत दाखिल की गई है।

अमेरिका में दिए गए बयान पर विवाद

राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए पगड़ी और कड़ा पहनने तथा गुरुद्वारे जाने के अधिकार को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह सवाल केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि सभी धर्मों से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर भी

टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी।

दोनों पक्षों ने रखे तर्क

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। फिलहाल अदालत ने याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, यह अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

मूसानगर के मां मुक्ता देवी मंदिर में विवाद, डीएम ने दिए जांच के आदेश

➔ नवरात्र को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश, एसडीएम भोगनीपुर और पुलिस अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित प्राचीन मुक्ता देवी/मुकेश्वरी माता मंदिर में निर्माण और जीर्णोद्धार को लेकर उठे विवाद को जिलाधिकारी कपिल सिंह ने गंभीरता से लिया है। स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट में मंदिर परिसर में पुराने भवनों को गिराकर नए निर्माण कराने, संरक्षित स्मारक के नियमों के उल्लंघन की आशंका और मंदिर की जीर्णोद्धार समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने एसडीएम भोगनीपुर और पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी नवरात्र को देखते हुए मंदिर परिसर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरतने को कहा है।

जानकारी के अनुसार, यमुना नदी के तट पर स्थित मुक्ता देवी मंदिर धार्मिक आस्था के साथ पुरातात्विक महत्व भी रखता है।

इसे उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में तीन दिसंबर 1982 की अभिसूचना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संरक्षित स्मारक में पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना निर्माण, परिवर्तन या संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में मंदिर परिसर में

संरक्षित स्मारक में मनमाने निर्माण और जीर्णोद्धार को लेकर उठे सवाल, चढ़ावे के हिसाब-किताब की भी जांच की जरूरत

नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर

मंदिर में नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखना भी अहम है। रिपोर्ट में मंदिर समिति, पुजारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की आशंका का जिक्र किया गया है। ऐसे में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जांच के दौरान मंदिर परिसर की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की वैधता, समिति से जुड़े दस्तावेजों और लगाए गए आरोपों की वास्तविकता की पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों से जांच के बाद रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि मंदिर परिसर में निर्माण को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं और समिति के कामकाज के संबंध में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट में मंदिर की जीर्णोद्धार समिति की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीन अक्तूबर को समिति की बैठक में एसडीएम भोगनीपुर और क्षेत्राधिकारी की अनुपस्थिति में मंदिर परिसर में मुकेश्वरी माता के सामने बने कमरों को गिराकर नए सिरे से निर्माण कराने का निर्णय लिए जाने का आरोप है। इसके अलावा पर्यटन विभाग से निर्माण कार्यों के लिए

धनराशि स्वीकृत कराने के प्रयास की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। अब यह जांच का विषय होगा कि प्रस्तावित निर्माण के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति ली गई है या नहीं और संरक्षित स्मारक के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

दान और चढ़ावे के हिसाब पर भी उठे सवाल

रिपोर्ट में मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के हिसाब-किताब में कथित अनियमितता, संरक्षित क्षेत्र में दुकानों के निर्माण और मंदिर की सामग्री गायब होने जैसे



आरोपों का भी उल्लेख है। मंदिर समिति के पंजीकरण, पदाधिकारियों की सूची, बैंक खातों, ऑडिट रिपोर्ट और पर्यटन विभाग से स्वीकृत योजनाओं के विवरण की जांच किए जाने की जरूरत बताई गई है।

इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खबरें : एक नजर में

युवक से मारपीट में तीन पर एफआईआर

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना के लाल गांव निवासी अहिबर्न सिंह ने गांव के रूप सिंह, उनकी पत्नी रामायणश्री और रसूलपुर निवासी अशोक कुमार के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि 12 अक्तूबर की शाम करीब छह बजे गाजियाबाद से घर लौटने पर तीनों लाठी-डंडे लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

दो लोगों पर मारपीट का आरोप

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के सिठरपुरवा निवासी टिंकु उर्फ ओंकार नाथ तिवारी ने गांव के दो लोगों के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि 15 अक्तूबर को दोपहर करीब तीन बजे हिमांशु दुबे और प्रियांशु दुबे पूर्व में हुए विवाद को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने उनके साथ मारपीट की। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

चार लोगों ने मिल कर भाई-बहन को पीटा



कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गोकुल निवादा मजरा कहंजरी खुर्द निवासी शिवानी कमल ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि नौ अक्तूबर को वह अपने भाई रोहित कुमार के साथ दवा लेने कहंजरी जा रही थी। रास्ते में कहंजरी निवासी जयवंद यादव, पंकज यादव, राजन यादव और जगमन निवादा निवासी जीतू ने उन्हें घेर लिया और रोहित को गाली देने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने रोहित के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंची शिवानी को भी पीटा दिया। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि चारों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़ से लेकर कबड्डी तक बच्चों ने दिखाया दम

न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। मलासा विकासखंड की न्याय पंचायत गुरगांव के सविनिलयन विद्यालय बिदखुरी में शुक्रवार को न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने दौड़, कबड्डी और लंबी कूद समेत कई स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कबड्डी में बिदखुरी की टीम ने सभी वर्गों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा।

प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेविका आदेश कुमारी, अलंकृत जनकल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष वंदना सचान और समाजसेविका किशोरी त्रिवेदी ने किया। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ में अंडां के आयुष बालक वर्ग में प्रथम रहे, जबकि बालिका वर्ग में बिदखुरी की सलोनी ने बाजी मारी। 100 मीटर दौड़ में डोभा के आदित्य और बालिका वर्ग में हरामऊ की गुंजन ने पहला स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ में गुरगांव के प्रांजुल प्रथम रहे।



जूनियर स्तर की 100 मीटर दौड़ में बिदखुरी के अहम ने पहला और अकोढ़ी के शिखर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में हरामऊ की अंशिका प्रथम रहीं। 200 मीटर बालक वर्ग में बिदखुरी के अहम और बालिका वर्ग में अकोढ़ी की महक ने प्रथम स्थान हासिल किया। लंबी कूद में हरामऊ के शोभित बालक वर्ग में

अव्वल रहे, जबकि बालिका वर्ग में अकोढ़ी की सजल ने पहला स्थान प्राप्त किया। समापन पर ग्राम प्रधान विमल सचान ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र पाल ने किया।

आयोजन नोडल शिक्षक रजनीश सक्सेना की देखरेख में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सचान, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सर्वेश कटियार, एआरपी अधिनी कटियार, योगेंद्र त्रिवेदी, कुलदीप सैनी, सुरेंद्र कटियार समेत शिक्षक, निर्णायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

वाराणसी में जुआ अड्डों के संचालन का मामला गरमाया, पुलिस आयुक्त से मिले अधिवक्ता

स्वराज इंडिया

फालोअप

» जैतपुरा, आदमपुर और कैट थाना क्षेत्रों में जुआ संचालित होने का आरोप, पुलिस और एसओजी-2 की भूमिका की जांच कराने की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

वाराणसी। वाराणसी के जैतपुरा, आदमपुर और कैट थाना क्षेत्रों में कथित जुआ अड्डों के संचालन को लेकर पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता शिवम पाण्डेय ने अधिवक्ता रोहित कृष्ण यादव की ओर से पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में संबंधित क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कथित जुआ संचालन और भारी धनराशि के लेन-देन का आरोप लगाया गया है।

स्वराज इंडिया की ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग का समाज में गहरा प्रभाव



पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर नजर

ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने पुलिस आयुक्त से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। अब मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर नजर है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही सामने आएगी। संबंधित लोगों का पक्ष और पुलिस प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

साथ ही स्थानीय पुलिस और एसओजी-2 की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी वरिष्ठ अधिकारी से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है।

दीपक यादव समेत कई लोगों के नाम शिकायत में शामिल

ज्ञापन में दीपक यादव उर्फ कल्लू, अन्नू यादव, निक्की जायसवाल, किशन महाराज,

वाराणसी में सज रहा करोड़ों का जुआ तीन थाना क्षेत्रों में बेखौफ कारोबार

जैतपुरा, आदमपुर और कैट में जूआ अड़े संचालित होने का दावा, स्थानीय पुलिस और एसओजी-2 की भूमिका पर उठे सवाल

[illegible]

कथित तौर पर जुग का कारोबार चलने की खास कला जा रही है। यहाँ, आदमपुर सेमी में गंगा किनारे जुआ सिस्टिकेंट के राक्षस होने के आरोप हैं। कैट जैसे ज्वलत दलालों में भी कथित जुआ अर्जु के संकलन को लेकर सवाल उठता जा रहे हैं। इन आरोपों की निष्पत्ति जांच से हो

राजू, विजय सोनपापड़ी, शिवम

समेट कई लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है। शिकायत में

इन लोगों की कथित भूमिका की
ने की मांग की गई है। हालांकि,

स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संलिप्तता जांच और साक्ष्यों के

ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की मांग

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि संबंधित क्षेत्रों में अवैध जुआ संचालन की पुष्टि होती है, तो इसके संचालकों और आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि कहीं किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी की संलिप्तता अथवा लापरवाही तो नहीं है।

समाधान दिवस: नहीं पहुंचे डीएम, फरियादी भी कम आए

जिलाधिकारी का इंतजार करते रहे फरियादी, अन्य अधिकारियों को सौंपे शिकायती पत्र

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखने की उम्मीद लेकर भोगनीपुर तहसील पहुंचे फरियादियों को शनिवार को निराश होना पड़ा। तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी कपिल सिंह नहीं पहुंचे। ऐसे में काफी देर तक उनके आने की आस लगाए बैठे फरियादियों को अपनी शिकायतें अन्य अधिकारियों के सामने रखनी पड़ीं। डीएम की गैरमौजूदगी के चलते समाधान दिवस में फरियादियों की संख्या भी कम नजर आई।

संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य एक ही स्थान पर जनसमस्याओं को सुनकर उनका समयबद्ध निस्तारण कराना है। इसी उम्मीद में



फरियादी की समस्या सुनते एडीएम

लोग अपनी शिकायतें लेकर तहसील पहुंचते हैं। फरियादियों को उम्मीद रहती है कि जिलाधिकारी के सामने समस्या रखने पर

संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शनिवार



को भी कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के नहीं आने से उन्हें दूसरे अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर संतोष करना पड़ा।

डीएम की अनुपस्थिति में समाधान दिवस में मौजूद अधिकारियों के सामने शिकायतें दर्ज रखी गईं। अब सवाल यह है कि फरियादियों की ओर से दिए गए शिकायती पत्रों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई होती है और लोगों को उनकी समस्याओं से कब तक निजात मिलती है। समाधान दिवस की सार्थकता तभी है, जब शिकायतों का समय से निस्तारण हो और

फरियादियों को बार-बार तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। समाधान दिवस में एडीएम वित्त दिग्विजय सिंह, जिला परियोजना निदेशक अनुरुद्ध सिंह चौहान, उपजिलाधिकारी देवेन्द्र सिंह, तहसीलदार जितेंद्र, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत कुमार, समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह, खंड विकास अधिकारी संजय कनौजिया, खंड शिक्षा अधिकारी सपना सिंह, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता आलोक प्रकाश, नगर पालिका ईओ सुनील कुमार, अमरौधा ईओ नीति त्रिपाठी और डीपीआरओ विकास पटेल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मरीजों की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, चार कर्मियों का वेतन रोका

» मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में लापरवाही पर कार्रवाई, चारों को कारण बताओ नोटिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) डेरापुर के मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में मरीज को जमीन पर लिटाने

और कर्मचारियों की लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पुनीत पांडेय ने दो स्टाफ नर्स, एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड का 14 अक्टूबर का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही चारों कर्मचारियों को

कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। मरीज को जमीन पर लिटाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने कर्मचारियों को मरीजों और उनके तीमारदारों की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की गरिमा और अस्पताल की छवि से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



नवंबर में आएगी नई आयुष नीति-2026

निवेश और शोध को मिलेगा बढ़ावा

❖ पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे आयुष अस्पताल, निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी और स्टांप शुल्क में छूट देने की तैयारी, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस केंद्रों पर रहेगा विशेष जोर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नई आयुष नीति-2026 लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सरकार की योजना नवंबर में इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाने की है। नई नीति के माध्यम से आयुष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं के

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

नीति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत आयुष अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की योजना शामिल है। इससे सरकारी संसाधनों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और आधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों के विकास का रास्ता खुल सकता है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने के साथ इस क्षेत्र को निवेश और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।

निवेशकों को मिल सकती हैं कई रियायतें

नई नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी, जमीन



प्रतीकात्मक फोटो

खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट और नई यानी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए विशेष सुविधाएं देने की योजना है। इससे आयुष अस्पतालों, औषधि निर्माण इकाइयों, उपचार केंद्रों और अन्य संबंधित कारोबार में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि,

इन सुविधाओं का अंतिम स्वरूप नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद स्पष्ट होगा। शोध और दवाओं की गुणवत्ता पर जोर नई आयुष नीति में अनुसंधान को प्रमुख स्थान देने की तैयारी है। आयुष औषधियों की जांच, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शोध

संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी सहित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना भी है। इससे प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिल सकती है।

पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का होगा विस्तार

नीति में पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस केंद्रों को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बेहतर आधारभूत सुविधाओं, वैज्ञानिक शोध और गुणवत्ता मानकों से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार के अनुसार, नीति का मसौदा तैयार है और इसे नवंबर में मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की तैयारी है। प्रस्तावित नीति से प्रदेश में आयुष सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और संबंधित उद्योग के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।

इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मुठभेड़ में झपटमारी का आरोपी घायल

» महिला का हैंडबैग छीनकर हुआ था फरार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली; 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज होने का दावा



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इटावा। महिलाओं से राह चलते छिनैती और झपटमारी करने वाले अपराधियों के खिलाफ इटावा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। भरथना क्षेत्र में महिला का हैंडबैग छीनकर फरार हुए आरोपी का शुक्रवार रात पुलिस से सामना हो गया। पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान रोकने पर बाइक सवार आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक, भरथना थाना क्षेत्र में गंगौरा की ओर जाने वाले मार्ग पर भरथना रोड के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान सामने से बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। आरोप है कि बाइक सवार ने गति बढ़ाकर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया।

मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान

कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया समेत विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या, अपहरण, फिरोती, धमकी, धोखाधड़ी और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा और सड़क पर होने वाली छिनैती व झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सदियों की निगरानी और चेकिंग बढ़ाई जा रही है।

अनुज शुक्ला निवासी थाना किशनी, जिला मैनपुरी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल और 700 रुपये नकद बरामद किए हैं।

मोहन पेड़ा में खाद्य विभाग की कार्रवाई नोटिस तक सीमित!

❖ कुछ माह पहले फफूंद लगी मिठाई बेचने का भी लगा था आरोप, दोबारा चूहों वाला वीडियो वायरल होने पर विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

स्वराज इंडिया
फालोअप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र स्थित मशहूर मिठाई प्रतिष्ठान मोहन पेड़ा में चूहों के मिठाई खाते वीडियो ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मिठाई के काउंटर में घुसकर चूहे के मिठाई खाते वीडियो के प्रसारित होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और काउंटर में रखी मिठाइयों को नष्ट कराया। दुकान संचालक को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन विभाग की कार्रवाई अब तक नोटिस तक सीमित नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि इसी प्रतिष्ठान पर कुछ माह पहले भी फफूंद लगी मिठाई बेचने का आरोप लगा था। उस समय भी शिकायत के बावजूद कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित रहने के आरोप सामने आए थे। अब दोबारा गंदगी और चूहों की मौजूदगी का वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मशहूर प्रतिष्ठान में मिठाइयों के बीच चूहों की मौजूदगी खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और ग्राहकों की सेहत के लिहाज से गंभीर मामला है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई केवल मिठाइयां नष्ट कराने और नोटिस जारी करने तक ही सीमित रहेगी? यदि पहले भी इसी प्रतिष्ठान में खराब मिठाई बेचने की शिकायत सामने आई थी, तो उसके बाद नियमित निगरानी कितनी प्रभावी रही? खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी केवल शिकायत मिलने या वीडियो प्रसारित होने के बाद मौके पर पहुंचने तक सीमित नहीं है। प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण की नियमित जांच भी जरूरी है। अब देखना होगा कि विभाग मामले में आगे



मलवा के मशहूर मोहन पेड़ा में चूहों का वीडियो वायरल

❖ डिस्पेंस काउंटर में रखी मिठाइयों पर चूहों की चक्कनकदमी से ग्राहकों में नाराजगी, खाद्य सुरक्षा पर उठे सवाल



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र स्थित मशहूर मिठाई प्रतिष्ठान मोहन पेड़ा में चूहों के मिठाई खाते वीडियो ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मिठाई के काउंटर में घुसकर चूहे के मिठाई खाते वीडियो के प्रसारित होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और काउंटर में रखी मिठाइयों को नष्ट कराया। दुकान संचालक को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन विभाग की कार्रवाई अब तक नोटिस तक सीमित नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि इसी प्रतिष्ठान पर कुछ माह पहले भी फफूंद लगी मिठाई बेचने का आरोप लगा था। उस समय भी शिकायत के बावजूद कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित रहने के आरोप सामने आए थे। अब दोबारा गंदगी और चूहों की मौजूदगी का वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मशहूर प्रतिष्ठान में मिठाइयों के बीच चूहों की मौजूदगी खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और ग्राहकों की सेहत के लिहाज से गंभीर मामला है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई केवल मिठाइयां नष्ट कराने और नोटिस जारी करने तक ही सीमित रहेगी? यदि पहले भी इसी प्रतिष्ठान में खराब मिठाई बेचने की शिकायत सामने आई थी, तो उसके बाद नियमित निगरानी कितनी प्रभावी रही? खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी केवल शिकायत मिलने या वीडियो प्रसारित होने के बाद मौके पर पहुंचने तक सीमित नहीं है। प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण की नियमित जांच भी जरूरी है। अब देखना होगा कि विभाग मामले में आगे

क्या कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।

अवध विश्वविद्यालय में छात्राओं से 'बैड टच' के आरोपों की जांच करेंगे रिटायर्ड जज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

चार छात्राओं की शिकायत पर प्रोफेसर निलंबित, तीन महीने में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट

अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग की छात्राओं से कथित अशोभनीय व्यवहार और यौन उत्पीड़न के मामले की जांच अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपी है। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। जांच में छात्राओं की शिकायतों, लगाए गए आरोपों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।

विश्वविद्यालय में यह मामला फाइन आर्ट्स विभाग की चार छात्राओं की शिकायतों



के बाद सामने आया।

छात्राओं ने अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव पर अनुचित तरीके से छूने, अपने कक्ष में बुलाने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने जैसे आरोप लगाए हैं।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुलपति प्रो. बिजेंद्र सिंह ने आंतरिक जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर को निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि में उन्हें विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग से संबद्ध किया गया है।

इससे पहले विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने भी मामले की जांच शुरू की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-

निर्देशों के तहत शिकायतों की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जांच से मामले के विभिन्न पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल की उम्मीद है।

दूसरी ओर, आरोपों का सामना कर रहे प्रोफेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश होने की आशंका भी जताई है। ऐसे में जांच समिति के सामने शिकायतकर्ताओं के आरोपों और संबंधित पक्ष के दावों की निष्पक्ष जांच करना महत्वपूर्ण होगा। मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

जिला अस्पताल में डॉक्टर पर इंटरन छात्रा से अभद्रता का आरोप

» नशे में होने का दावा, विरोध के बाद पहुंचा अस्पताल प्रशासन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल



के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक डॉक्टर इमरजेंसी ओपीडी में पहुंचा था। वह खुद को श्रीराम चिकित्सालय का डॉक्टर बता रहा था। आरोप है कि वहां मौजूद एक इंटरन छात्रा पर उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की।

इससे आहत छात्रा रोते हुए अपने साथियों के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिला अस्पताल में एक डॉक्टर पर इंटरन छात्रा के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है।

डॉक्टर के नशे में होने का भी दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो

साथी छात्राओं ने विरोध किया तो डॉक्टर ने कथित टिप्पणी को लेकर सफाई दी।

उसका कहना था कि वह जिला अस्पताल में अपने जूनियर से मिलने आया था और बातचीत के दौरान छात्रा को गलतफहमी हुई। मौके पर अस्पताल के अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। फिलहाल छात्रा की ओर से लिखित शिकायत दिए जाने की जानकारी नहीं है।

देवकाली बाईपास चौराहे पर अंग्रेजी वाईन शाप का उद्घाटन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। देवकाली बाईपास चौराहे पर अंग्रेजी वाईन शाप का उद्घाटन कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर दुकान के लाइसेंसधारी रवि पांडेय मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने उपस्थित लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान दुकान के संचालन से जुड़े लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। देवकाली बाईपास चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर मौजूद लोगों ने भी सहभागिता की। विष्णु पांडेय, आनंद कुमार पांडेय, लल्लन यादव, इंजीनियर नीबू लाल, गिरजेश पांडेय और आशुतोष कनौजिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

राम मंदिर के 150 में से 148 निर्माण कार्य पूरे

15 नवंबर तक परकोटा और फसाड लाइटिंग का लक्ष्य

» एलएंडटी ने ट्रस्ट को सौंपे आवश्यक अभिलेख, बारिश से प्रभावित हुआ परकोटे की छत पर वॉटर ट्रीटमेंट का काम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। कुल 150 निर्माण कार्यों में से 148 पूरे हो चुके हैं। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने आवश्यक अभिलेखों के साथ इन कार्यों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब परकोटे का निर्माण प्रमुख कार्य के रूप में शेष है। शुक्रवार को मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परकोटे का निर्माण और मंदिर व परकोटे की फसाड लाइटिंग 15 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। बारिश के कारण परकोटे की छत पर वॉटर ट्रीटमेंट का काम प्रभावित हुआ है। इसके



अधूरे रहने से परकोटे का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। मौसम अनुकूल होने पर काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली पर मंदिर की नक्काशी और स्थापत्य की खूबसूरती को उभारने के लिए विशेष रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एलएंडटी के भुगतान, निर्माणाधीन ऑडिटोरियम

और म्यूजियम की प्रगति पर भी चर्चा होगी। नृपेंद्र मिश्र के अनुसार, विजय स्तंभ और शहीद स्मारक का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि इनके परिसर में उद्यान और हॉर्टिकल्चर से जुड़े कुछ कार्य बाकी हैं। मध्वाचार्य द्वार का निर्माण करीब 80 प्रतिशत पूरा हो गया है।

तकनीकी जांच के बाद होगा हस्तांतरण

परकोटे का निर्माण पूरा होने के बाद एलएंडटी ड्राइंग, डिजाइन,

निर्माण संबंधी अभिलेख और वित्तीय विवरण ट्रस्ट को सौंपेगी।

इसके बाद ट्रस्ट के परियोजना इंजीनियर निर्माण कार्यों की जांच करेंगे। आवश्यक मानकों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही हस्तांतरण स्वीकार किया जाएगा।

शिक्षक मतदाता सम्मेलन में बोले पंकज चौधरी, हर वोट लोकतंत्र की ताकत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए संपर्क-संवाद पर जोर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित शिक्षक मतदाता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को जीवन की दिशा देने के साथ राष्ट्र का भविष्य भी गढ़ते हैं। लोकतंत्र की असली ताकत मतदाताओं का विश्वास है और प्रत्येक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत



की बढ़ती भूमिका, योग दिवस और जी-20 के आयोजनों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के पारदर्शी स्थानांतरण, मृतक आश्रितों को लाभ देने की प्रक्रिया सरल बनाने तथा विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार का भी जिक्र किया।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए

चौधरी ने समाजवादी पार्टी को मुद्दाविहीन बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 17 और 24 अक्टूबर को आयोजित होने

वाले विशेष शिविरों में पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने में सहयोग करने की अपील की। सम्मेलन में क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी, प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह और अवधेश श्रीवास्तव, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, पूर्व सांसद लखू सिंह तथा जिला पंचायत प्रशासक रेली सिंह सहित कई जिलों के पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।

संपर्क-संवाद से मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति

अवध विश्वविद्यालय के श्रीराम शोध पीठ में आयोजित बैठक में पंकज चौधरी ने शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा। उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। बैठक में अबेडकरनगर, गोडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अनेरी और सुल्तानपुर की जिला इकाइयों के पदाधिकारी शामिल हुए।

रूस से तेल खरीदने वाले देशों को ट्रंप की राहत, भारत पर टला 100% टैरिफ

राष्ट्रीय हित का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस संबंधी प्रतिबंधों पर लगाई रोक, भारत-चीन समेत बड़े ऊर्जा आयातक देशों को राहत, महंगे तेल से घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करने की कोशिश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं। भारत समेत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों को इससे बड़ी राहत मिली है। ट्रंप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों और रूसी तेल-गैस के खरीदारों पर शुल्क लगाने से जुड़े नए अमेरिकी कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने से छूट देने का आदेश जारी किया है।



भारत को क्या मिली राहत?

- रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी दंडात्मक शुल्क का तत्काल खतरा टला।
- भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क का जोखिम फिलहाल कम हुआ।
- तेल आयात के विकल्पों और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत को राहत मिली।
- अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत के लिए कुछ अतिरिक्त गुंजाइश बनी।

इससे भारत पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क का तत्काल खतरा टल गया है। दरअसल, अमेरिका में पिछले महीने पारित लिंडसे ओ. ग्राहम सेंकशनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। इस कानून के अंतर्गत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले चुनिंदा देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान था। इसका उद्देश्य यूक्रेन के



खिलाफ युद्ध को लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसकी ऊर्जा से होने वाली कमाई को प्रभावित करना था। नए प्रावधानों के प्रभावी होने की समयसीमा 18 अक्टूबर के आसपास थी। हालांकि, ट्रंप ने समयसीमा से पहले ही महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगा दी।

भारत के लिए यह फैसला इसलिए अहम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई थी। इससे भारतीय तेल कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपेक्षाकृत सस्ता तेल हासिल करने का विकल्प मिला। भारत अपनी बड़ी आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में रूसी तेल की खरीद पर अमेरिकी दंडात्मक शुल्क

लगने से भारतीय निर्यात, व्यापारिक संबंधों और ऊर्जा लागत पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था। अब तत्काल खतरा कम होने से भारत को राहत मिली है।

ट्रंप के फैसले के पीछे घरेलू आर्थिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिका में ईंधन महंगा होने के दबाव के बीच रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर सख्ती से अमेरिकी उपभोक्ताओं की लागत बढ़ने की आशंका थी। इसके अलावा, नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ईंधन की कीमतों अमेरिकी प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मुद्दा हैं।

हालांकि, इस फैसले को भारत के लिए स्थायी शुल्क-मुक्ति या अमेरिका के साथ व्यापारिक विवाद का पूर्ण समाधान

ट्रंप ने क्यों बदला रुख?

- महंगे ईंधन का दबाव- तेल की कीमतों में तेजी से अमेरिकी उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र की लागत बढ़ने की आशंका थी।
- घरेलू राजनीति- मध्यावधि चुनावों से पहले ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण अमेरिकी प्रशासन के लिए अहम है।
- रूस पर दबाव बनाम आर्थिक हित- रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की जरूरत के बीच अमेरिका को संतुलन साधना पड़ रहा है।
- भारत के साथ संबंध- भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक और व्यापारिक साझेदार पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ सकता था।

नहीं माना जा सकता। ट्रंप का आदेश भविष्य में प्रतिबंधात्मक कदम उठाने की गुंजाइश बनाए रखता है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, रूस के साथ व्यापार और अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।

कोटा में भीषण सड़क हादसा, नाले में गिरी मिनी बस, आठ की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में शनिवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों का उपचार किया जा रहा है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मिनी बस में मध्य प्रदेश के भोपाल और बैतूल क्षेत्र के यात्री सवार थे। सभी राजस्थान में खादूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा शनिवार सुबह करीब छह बजे कोटा जिले में सिमलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर खंभा संख्या 384 के आसपास हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन में लगभग 20 से 25 यात्री सवार थे। हालांकि, यात्रियों की वास्तविक

- भोपाल से खादूश्यामजी के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, 15 से अधिक घायल
- चालक को झपकी आने से हादसे की आशंका, क्रेन से निकाले गए यात्री

संख्या को लेकर अलग-अलग सूचनाएं सामने आई हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि वाहन चलाते समय चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद मिनी बस सड़क से उतरकर नाले में जा गिरी। हालांकि, दुर्घटना का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। नाले में पानी और कीचड़ जमा होने के कारण बचाव दल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्षतिग्रस्त वाहन को बाहर निकालने और उसमें फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पुलिस और अन्य राहतकर्मियों ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।

17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यूपी समेत पांच चुनावी राज्यों पर नजर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का निर्देश दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे पांच चुनावी राज्य भी शामिल हैं। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य पात्र मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने जा रहे नागरिकों के नाम सूची में शामिल करना तथा मौजूदा प्रविष्टियों में त्रुटियों को दूर करना है।

आयोग के अनुसार, इस पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी 2027 को पात्रता की आधार तिथि निर्धारित किया गया है। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, पहले से दर्ज विवरण में सुधार कराने और अपात्र प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की



17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलेगा अभियान

इस विशेष पुनरीक्षण के दायरे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिम्मेदारी दी है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटने न पाए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे।

नवंबर में जारी होगी प्रारूप सूची

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया दो नवंबर तक पूरी की जानी है। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा विवरण में सुधार से संबंधित दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक स्वीकार की जाएंगी। इनके निस्तारण के लिए 28 दिसंबर की समयसीमा निर्धारित की गई है। पूरी प्रक्रिया के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने पहली बार पात्र होने जा रहे युवाओं को भी ध्यान में रखा है। एक जनवरी 2027 के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 की पात्रता तिथियों के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। इससे 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनने की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। जिला स्तर पर सहयता केंद्रों के माध्यम से प्रवासियों, वृद्धों और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को भी आवेदन संबंधी मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

